इससे देश के युवकों को रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान कराये जा सकते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार द्वारा स्थाई रूप से कपास का निर्यात किय जाने का निर्णय लेने के क्या कारण है और इस निर्णय के फलस्वरूप देश को क्या लाभ होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कपास के निर्यात की एक दीर्घकालिक नीति है जिसका अनुमोदन वर्ष 1990 में मंत्रीमंडल कि निर्यात नीति संबंधी समिति द्वारा किया गया था, इस नीति में यह निर्धारित है कि प्रत्येक कपास मौसम में कपास की 5 लाख गांठों का निर्यात किया जाएगा तथा उसके बाद की रिलीज कपास की घरेलू उपलब्धता तथा कीमतों को ध्यान में रखने के बाद की जाएगी। इस निर्यात की नीति के तीन मुख्य उद्देश्य हैं : (क) कपास की कीमतों को स्थिर बनाना जो कि उपजकर्ताओं और उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं ; (ख) कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करना ; तथा (ग) कपास के एक स्थाई सप्लाईकर्ता के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की उपस्थिति बनाए रखना।

कपास की बर्बादी

1082. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कपास की ओटाई सुविधा के अभाव में प्रति वर्ष कपास की 5 लाख गांठें बर्बाद हो जाती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या मूल्यांकन है ;

(ग) क्या यह भी सच है देश में कपास उत्पादन की औसत दर अन्य कपासोत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है ; और

(घ) यदि हां, तो देश में प्रति हैक्टेयर कपास का कितना उत्पादन होता है और विश्व में कपास की औसत उत्पादन दर कितनी है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कपास उपजाने वाले कुछ क्षत्रों में संसाधन सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण किसानों को विपणन तथा संसाधन के लिए बहुत दूर ले जाना पड़ता है, जिसके कारण उनको ले जाने में काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे अपशिष्ट से होने वाली क्षति के सही आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत में कपास का औसत उत्पादन विश्व में कपास उपजाने वाले प्रमुख देशों की तुलना में कम है जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है।

देश का नाम	उपज (किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)	
	1992–93	1993–94
1	2	3
1. इजरायल	1771	1688
2 आस्ट्रेलिया	1510	1408
3 सीरिया	1094	1037
4. मिस्र	1001	906

1	2	3	4
5.	टर्की	900	925
6.	उजबेकिस्तान	783	771
7.	संयुक्त रा. अमेरिका	783	749
8.	कजाकिस्तान	716	636
9.	चीन	560	810
10.	पाकिस्तान	555	665
11.	भारत	300	287
	विश्व औसत	554	578

Compulsory backing of Urea and Cement in jute bags

1083. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Jute Backaging Act makes it mandatory on the fertilizer units to pack their entire urea production and 65 per cent of cement output only in jute bags;

(b) if so, whether Government are aware that these units are blatantly violating the provisions of this Act; and

(c) if so, what steps Government propose to take against such violations?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) In the case of fertilizer units, it is mandatory to pack their entire urea production in jute bags only. The obligation imposed on cement units located beyond 1200 ms. away from Calcutta is to pack 65 per cent of their production in jute bags (70 per cent for units situated within 1200 ms. from Calcutta) with exemption to mini-cement plants having manufacturing capacity upto 100 tonnes per day.

(b) Most of the cement units and some of the urea manufacturing units are violating the provisions of this Act by not using jute bags as required under this Act.

(c) Showcause notices have been issued from time to time against erring units for such violations.

Welfare scheme under handloom development programme in Madhya Pradesh

1084. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Government have formulated any welfare scheme for tribal dominated and backward districts of M. P. under the Handloom Development Programme;

(b) if so, the details thereof and the time by when these welfare schemes are likely to be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) All the Welfare Schemes formulated by the Government of India for handloom weavers are available for weavers through out the country including these from tribal dominated and back-ward districts of Madhya Pradesh.

(b) On the basis of proposals received from Government of Madhya Pradesh Central assistance has been released to the State During the year 1992-93 and